

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 12 - 12 - 2025

कार्यालय - बृजमोहन अग्रवाल, संसद सदस्य, रायपुर, लोकसभा

### **बृजमोहन अग्रवाल ने संसदीय समिति की बैठक में 'भविष्य के लिए तैयार' AI शिक्षा और नैतिक उपयोग पर दिया जोर**

- सरकार का लक्ष्य: व्यक्तिगत, सुलभ और समावेशी शिक्षा के लिए AI का एकीकरण
- समिति का सुझाव: सभी धाराओं के लिए अनिवार्य हो AI साक्षरता
- डिजिटल विभाजन को पाटने और क्षेत्रीय भाषाओं में AI शिक्षा पर विशेष फोकस
- शिक्षकों की निरंतर अपस्किनिंग और नैतिक AI फ्रेमवर्क की आवश्यकता

**नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2025** – संसदीय स्थायी समिति (शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल) ने आज सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा "शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभाव और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने की रणनीतियां" था।

बैठक के दौरान, मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शिक्षा में AI की भूमिका पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि AI का उपयोग सीखने में आने वाली बाधाओं, शिक्षकों की कमी और बहुभाषी विविधता को संबोधित करने के लिए किया जाना चाहिए।

अग्रवाल ने टियर 2 और 3 शहरों में 'IndiaAI Data Labs' की स्थापना और बुनियादी ढांचे की तत्परता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को भी शहरी छात्रों के समान ही AI शिक्षा का लाभ मिले।

#### **समिति ने अधिकारियों के समक्ष पांच प्रमुख सुझाव रखे:**

1. भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने हेतु इंजीनियरिंग के अलावा कला, वाणिज्य और मानविकी सहित सभी धाराओं के पाठ्यक्रम में AI की बुनियादी जानकारी अनिवार्य की जाए।
2. डिजिटल अंतर को कम करने के लिए AI शिक्षण सामग्री भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
3. AI की तेज गति को देखते हुए शिक्षकों के लिए 'सतत व्यावसायिक विकास' (CPD) कार्यक्रम अनिवार्य होने चाहिए।
4. शोध में AI टूल्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में सख्त 'AI आचार संहिता' (Code of Conduct) लागू की जाए।

#### **बृजमोहन अग्रवाल ने कहा:**

"हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि AI का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े छात्र तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य केवल तकनीकी रूप से सक्षम कार्यबल तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए, हमने सुझाव दिया है कि AI साक्षरता को केवल तकनीकी विषयों तक सीमित न रखकर इसे सभी छात्रों के लिए अनिवार्य किया जाए और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि '**विकसित भारत**' का सपना साकार हो सके।"

मंत्रालय ने 'दीक्षा' (DIKSHA), 'तारा' (TARA), 'माई करियर एडवाइजर' (My Career Advisor) और 'ई-जादुई पिटारा' (e-Jaadui Pitara) जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफार्मों की सफलता को रेखांकित किया। 'तारा' जैसे टूल का उपयोग बच्चों के मौखिक पठन प्रवाह का आकलन करने के लिए किया जा रहा है, जबकि 'माई करियर एडवाइजर' छात्रों को AI-आधारित करियर मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।